पीएफसी

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्त वर्ष 17-18 की तीसरी तिमाही, सम्मेलन कॉल

15 मार्च, 2018

पीएफसी **एडेलेवेइस**

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की प्रबंधन टीम

- **श्री राजीव वर्मा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक**
- **श्री डी रवि, निदेशक (वाणिज्यक)**
- **श्री एन. बी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)**

संचालक: श्री कुणाल शाह- एडेलेवेइस

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

संचालक: देवियों और सज्जनों आप सभी का दिन मंगलमय हो।

मैं निदेशकों के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रबंधन के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ जिसकी मेजबानी एडेलवेइस सिक्योरिटीज लिमिटेड कर रहा है। मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि सभी सहभागियों की लाइनें केवल सुनने के मोड (लिसेन मोड) में रहेंगी और प्रस्तुति समाप्त होने के बाद आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। यदि कांफ्रेस-काल के दौरान आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो अपने टच टोन पर पहले स्टार (*) दबाएँ और उसके बाद शून्य (0) दबाकर आपरेटर को संकेत दें। कृपया ध्यान दें कि इस सम्मेलन की रिकार्डिंग की जा रही है। अब मैं सम्मेलन का संचालन एडेलवेइस सिक्योरिटीज लिमिटेड के श्री कुणाल शाह को सौंपता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद और अब महोदय आप संचालन करें।

कुणाल शाह: धन्यवाद, अनिकेत और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निदेशकों के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रबंध के संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस समय हमारे साथ पीएफसी के श्री राजीव शर्मा- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री एन. बी. गुप्ता- निदेशक (वित्त) और श्री डी. रवि निदेशक (वाणिज्य) मौजूद हैं जो आमतौर पर विद्युत क्षेत्र में हुए अद्यतन विकास और खासतौर पर पीएफसी से संबंधित अद्यतन बातों पर विचार-विमर्श करेंगे, भले ही वे मंत्रालय के निदेश पत्र से संबंधित हो या अन्य कोई नया विषय हो। इसलिए, महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है

कि शुरू-शुरू संक्षेप में दो शब्द कहें और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर (क्यू एंड ए) सत्र में प्रवेश करेंगे। महोदय, अब आप संचालन करें।

राजीव शर्मा: यह अवसर प्रदान करने के लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, इस सम्मेल काल (कांफ्रेंस काल) में मैं आप सबाक स्वागत करता हूँ। हमने यह कांफ्रेस-काल इसलिए बुलाई है कि हम पीएफसी को वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के निष्पादन, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों और संबंधित मीडिया रिपोर्टों, विद्युत क्षेत्र के आगे ले जाने के दृष्टिकोण के संबंध में अपने विचार आपसे साझा कर सकें। सबसे पहले, मैं पीएफसी के संबंध में कुछ झलकियों को साझा करना चाहता हूँ। व्यापार वृद्धि के मोर्चे पर हमने 10 प्रतिशत ऋण वृद्धि दर्शाई है। एनपीए के मोर्चे पर, जैसा कि हम एनपीए के व्युत्क्रमण के बारे में अपने पूर्ववर्ती कांफ्रेस काल में संकेत कर चुके हैं, को मुझे साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस वित्त वर्ष में अपने एनपीए में उल्लेखनीय कमी लाई है। वर्ष के आरंभ में 10.55 प्रतिशत के निवल एनपीए को वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में 4.23 प्रतिशत के चालू निवल एनपीए में से, सरकारी सेक्टर की एनपीए 2.04 प्रतिशत इसके उल्लेखनीय भाग के अगले वित्त वर्ष 2018-19 में विपरीत हो जाने की संभावना है, जैसाकि पहले संकेत दिया जा चुका है। 31 दिसंबर, 2017 को केवल 2.19 प्रतिशत निवल एनपीए निजी क्षेत्र के ऋण के रूप में है।

अपने पूर्ववर्ती कांफ्रेस कालों में मैंने यह भी दर्शाया था कि हम ऋण पोर्टफोलियो को विविधीकृत बनाने की ओर देख रहे हैं।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

तदनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के दौरान हमने 5400 मिलियन अमेरिकी डालर के ग्रीन बॉड एकत्र किए जो किसी भारतीय जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए 'इनौगरल बॉड' के लिए अब तक का सबसे कठिन मूल्य है। इसके अतिरिक्त, हमने 100 मिलियन अमेरिकी डालर के एफसीएनआर (बी) ऋण एकत्र किए। वित्त वर्ष 18 की चौथी तिमाही के दौरान हमने 250 मिलियन सिडिकेटेड लोन की कुछ विदेशी मुद्रा और 100 मिलियन का एफसीएनआर (बी) ऋण भी एकत्र किया है। 250 मिलियन अमेरिकी डालर का दूसरा विदेशी मुद्रा ऋण भी मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त, हम अपने मौजूदा 540 मिलियन अमेरिकी डालर की दूसरी विदेशी मुद्रा देयताओं को पुन: वित्त पोषित करने के बारे में विचार कर रहे हैं जिसके द्वारा निधियों की लागत और कम हो जाएगी। हम कैपिटल गेन बॉडों के जरिए भी निधियॉ जुटा रहे हैं जो 5.25 प्रतिशत के कूपन बॉड के रूप में हैं। इस लिखत के अंतर्गत हमने 200 करोड़ रूपए से अधिक रूपए जुटाए हैं। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में हमारी निधियों की औसत लागत में 13 बेसिस प्वाइंट कमी होकर 8.23 प्रतिशत से 8.10 प्रतिशत रह गई।

अब मैं आप लोगों के साथ तनत्व को दूर करने और उसके प्रभाव के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों को साझा करूँगा। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए मानक हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है क्योंकि पीएफसी एक एनबीसीएफ है। तथापि, चूँकि

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

हम अपनी अधिकांश निजी ऋण पंजिका के लिए बैंकों के सहायता संघ में है, इसलिए आरबीआई के ये मानक अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करेंगे।

अब मैं अपनी ऋण परिसंपत्ति बही के रूप में बताता हूँ। हमारी कुल ऋण परिसंपत्ति पोर्टफोलियो 2,62,000 करोड़ रूपए का है जिसमें से सरकारी क्षेत्र के ऋण 2,18,000 रूपए हैं जो कि मोटे तौर पर 83 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र के ऋण 44,000 करोड़ (अर्थात 17 प्रतिशत) हैं। 2,18,000 करोड़ के ऋण बुक के संबंध में सभी सरकारी क्षेत्र के लेनदार हमारी देयताएँ नियमित रूप से दे रहे हैं और केवल नामनात्र का अतिदेय है। इसके अतिरिक्त हम सरकारी क्षेत्र के देनदारों के संबंध में किसी तनाव की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं।

निजी क्षेत्र के 44,000 करोड़ रूपए की जानकारी के मामले में, 14,000 करोड़ रूपए का निजी क्षेत्र का ऋण (अर्थात 32 प्रतिशत) नियमित रूप से अपनी देयताओं का भुगतान कर रहे हैं और इन ऋणों के संबंध में कोई मुद्दा ही नहीं है। 30,000 करोड़ रूपए का निजी क्षेत्र के ऋण का शेष या तो एनपीए श्रेणी में है या पुनर्संचरित मानक श्रेणी या मानक श्रेणी में है। एनपीए मोटेतौर पर 8500 करोड़; है, पुर्नसंचरित मानक परिसंपत्तियाँ लगभग 15,500 करोड़ रूपए की है और मानक परिसंपत्तियाँ लगभग 6000 करोड़ रूपए की हैं।

अब पुनरुद्धार उपायों के रूप में इन 30,000 करोड़ रु. की ऋण परिसंपत्तियों में से 4250 करोड़ रुपए की 3335 मेगावाट की क्षमता वाली

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

लगभग सात परियोजनाओं का आईबीसी के अंतर्गत एनसीएलटी के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। ये सातों परियोजनाएँ पहले से ही एनपीए श्रेणी में है। ब्योरा इस प्रकार है- एक परियोजना में एनसीएलटी के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया चल रही है। दो परियोजनाओं में एनसीएलटी को याचिका दायर की गई है। चार परियोजनाओं में हम एनसीएलटी को दायर करने की प्रक्रिया में है। 25,750 करोड़ रुपए के शेष ऋण, जिसकी 16,000 मेगावाट की 22 परियोजनाएँ हैं, के लिए विभिन्न समाधान तंत्र चलाए जा रहे हैं जिनमें एसडीआर, एसडीआर से बाहर, 54ए जैसी पूर्ववर्ती आरबीआई स्कीमें चल रही हैं तथा अन्य रिजोलुशन तंत्र चल रहे हैं। प्रबंधन द्वारा अधिग्रहण के लिए कुछ परियोजनाएँ पहले से ही बोली की प्रक्रिया में हैं तथा प्रबंधन में परिवर्तन के लिए कुछ की बोली लगाई जाने वाली है। कुछ परियोजनाएँ पहले ही बंदोबस्त या पुनर्संरचना जैसे कार्यों के अंतर्गत हैं इसलिए हम आशान्वित हैं कि हम आरबीआई द्वारा निर्धारित 180 दिनों से पूर्व इन कुछ ऋण परिसंपत्तियों को पुनर्संरिचत करने या बंदोबस्त करने या बोली लगाने में सफल होंगे अन्यथा उसके बाद हमें एनसीएलटी से संपर्क करना पड़ेगा। हम इस बात को लेकर भी आशान्वित हैं कि ये सारी ऋण परिसंपत्तियॉ देनदार को अपेक्षाकृत कम नुकसान न पहुँचाते हुए एनसीएलटी के अंतर्गत पुनर्संरचित बंदोबस्त या बोली के अधीन होंगी जिसमें इन परियोजनाओं के 50 प्रतिशत से अधिक पीएफसी मोटेतौर पर 10,000 मेगावाट पर प्रारंभ होंगी। इन परियोजनाओं के 50 प्रतिशत से अधिक में पीपीए है और इन परियोजनाओं के 70 प्रतिशत से अधिक में एफसीए है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि 30,000 करोड़ रुपए की इन कुल 29 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं का कुल

एक्सपोजर 2000 करोड़ से कम होगा। इसलिए समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की 180 दिनों की सीमा रेखा इस समय ऐसे ऋणों पर लागू नहीं होती।

अब प्रावधान करने और आय की हानि का संबंध है। आमतौर पर विद्युत परियोजना में परियोजना लागत का 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत साम्या (इक्विटी) से पूरा किया जाता है और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत का वित्त पोषण ऋण द्वारा किया जाता है। इसलिए यदि हम इन परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत की कटौती (हेयरकट) का अनुमान लगाएँ, सीओडी, पीपीए, एफएमए के रूप में इन परियोजनाओं की सकारात्मक बातों के बावजूद देनदारों द्वारा हेयरकट उस सीमा तक कम होगा। इनमें से अधिकांश परियोजनाएँ एनपीए श्रेणी में हैं और वहॉ आय बुक नहीं की जा रही है, इसलिए भावी लाभ या ब्याज मार्जिन के संबंध में बहुत प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, हम पहले ही 30,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए एनपीए पुनर्संचित मानक परिसंपत्तियों के संबंध में लगभग 50000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुके है। पूरी ऋण बही में कुल प्रावधान लगभग 8500 करोड़ रुपए बैठता है। साथ ही वर्ष के अंत तक यह अपेक्षा है कि इन परिसंत्तियों के लिए संचयी प्रावधान में और वृद्धि हो जाएगी। इसलिए पीएफसी धीरे-धीरे अपना प्रावधान कर रहा है ताकि इन परियोजनाओं पर आनेवाली किसी कठिनाई से निपटा जा सके। इस प्रकार पीएफसी पर कोई आकस्मिक और उल्लेखनीय प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएलटी के तहत समाधान, 180 दिनों के समयावधि में आवश्यक है। इन समय सीमाओं पर विचार करते हुए यह परिकल्पना की गई है कि इन परियोजनाओं का समाधान वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ही हो जाएगा। समाधान प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर इन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन से नई आय परिसंपत्तियों का सृजन करने में मदद मिलेगी और इससे पीएफसी के वित्तपोषण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, विद्युत परियोजना परिसंपत्तियों की विपत्तिजनक स्थिति की बिक्री से बचने के लिए हम संयुक्त उद्यम की संभावना तलाश रहे हैं जो इन परियोजनाओं के लिए बोली लगा सकता है और उचित मूल्य पर इन परियोजनाओं का अधिग्रहण कर सकता है। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य इन परियोजनाओं का अधिग्रहण करना और मॉग परिदृश्य में सुधार होने तक इनका कार्यान्वयन और संचालन करना है और बेहतर मूल्यांकन के लिए बाद में इनकी बिक्री करना है। यह संयुक्त उद्यम दृष्टिकोण विचार-विमर्श के प्रारंभिक चरण में है जिसे आरबीआई और विधिक ढॉचे सहित सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने के बाद स्थापित किया जाएगा।

अब, मैं डिस्काम की वित्तीय स्थिति के बारे में उठाई गई चिंताओं, उनके बारे में हमरी जानकारी और पीएफसी पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ विचार साझा करता हूँ। इस संबंध में, हम यह बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर, 2017 को पीएफसी का 2400 करोड़ रुपए वितरण खंड में है जो

मोटेतौर पर हमारी ऋण बही का 9 प्रतिशत है, इस 9 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक कैपेक्स आधारित होगा और शेष गैर-कैपेक्स होगा।

अधिक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीआरसी) हानियों के कारण डिस्कामों द्वारा चुकौती में सामना की जाने वाली कठिनाई के संबंध में, मैं कहना चाहूँगा कि इस स्थिति के समाधान के लिए उदय स्कीम शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य वितरण कंपनियों का वित्तीय और प्रचालनात्मक दृष्टि से पूर्ण परिवर्तन लाना था।

'उदय' घाटे वाले डिस्कामों के मौजूदा ऋण को राज्य द्वारा वहन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, भविष्य में होने वाली हानियॉ भी राज्य द्वारा वहन की जानी है। इस प्रकार, डिस्कामों की वर्तमान हानियों का प्रबंधन उदय स्कीम द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एटी एंड सी हानियों के मानचित्र पर उदय स्कीम डिस्कामों की एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल किए गए हैं। साथ ही, उदय स्कीम में बैंकों और वित्तीय संस्था के निधीयन को डिस्कामों के पूर्ववर्ती वर्ष के 25 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।

इस प्रकार, डिस्कामों को गैर-कैपेक्स निधीयन करते समय, उदय स्कीम के अनुसार सुधार संबंधी प्राचल ऋण की मंजूरी की निबंधनों और शर्तों में शामिल किया जाता है। कैपेक्स के प्रयोजन से निधीयन उन कैपेक्स मदों के लिए होता है जो विनियामक द्वारा अनुमोदित किए गए होते हैं। इसके

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

अतिरिक्त, आज की तारीख तक, पीएफसी अपने संपूर्ण ऋण पोर्टफालियों के लिए आरबीआई प्रूडेंसियल मानकों का अनुसरण कर रहा है इसके साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से डिस्काम सर्विस देने में नियमित रहे हैं इसलिए भविष्य में कोई चूक की संभावना नहीं है।

मैं आप लोगों के साथ वितरण सेक्टर के दृष्टिकोण को साझा करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की है जो ग्रामीण और शहरी वितरण सेक्टर के विकास के लिए एक समेकित विद्युत विकास स्कीम है। जबकि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण परिवारों को चौबीस घंटे बिजली और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। आईपीडीएस से शहरी क्षेत्रों में एटी एंड सी हानियों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सौभाग्य स्कीम शुरू की है जिसका उद्देश्य देश के इच्छुक परिवारों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। इन सरकारी स्कीमों के माध्यम से वितरण सेक्टर में परिकल्पित कुल निवेश मोटे तौर पर लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए हैं। वितरण सेक्टर में सुधार के लिए भारत सरकार के प्रयास और पर्याप्त निवेश किए जाने से एसीएसआरएआरआर के बीच अंतराल और एटी एंड सी हानियों की कुल हानियों में कमी आई है।

चिंता की बात यह है कि वितरण कंपनियॉ विशेष रूप से एटी एंड सी हानियों के संबंध में अच्छा निष्पादन नहीं कर रही है, परंतु इस सेक्टर में उल्लेखनीय विकास हुआ है जो सभी पणधारकों के लिए अच्छा है। मैं उन

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

45 वितरण कंपनियों के संबंध में कुछ नम्बरों को साझा करूँगा जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ऑकड़े उपलबध करवाए हैं। उदय स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के 45,394 करोड़ रुपए की तुलना में 36,047 करोड़ रुपए के रूप में ब्याज के व्यय में कमी आने के प्रमुख कारण से कुल हानियों में 20 प्रतिशत कमी आई है। बिजली की बिक्री से वर्ष 2015-16 में 3,80,510 करोड़ रुपए की तुलना में 2016-17 में 4,09,703 करोड़ रुपए अर्थात लगभग 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। प्राप्त हुई सब्सिडी में अंतराल भी प्रति यूनिट 11 पैसे की कमी आई है- वर्ष 2015-16 में 39 पैसे प्रति यूनिट। आरएपीडीआरपी या आईपीडीएस के अंतर्गत जिन 1270 शहरों के लिए ऑकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 245 शहरों की एटी एंड सी हानियॉ 10 प्रतिशत से कम है- 247 शहरों की एटी एंड सी हानियॉ 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच हैं- 162 शहरों की एटी एंड सी हानियॉ 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश में वितरण सेक्टर के स्तर में सुधार और सुदृढ़ीकरण पर भारत सरकार द्वारा लगातार बल दिए जाने से आने वाले समय में निष्पादन प्राचलों में उल्लेखनीय सुधार होगा। अब आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते है। बहुत बहुत धन्यवाद।

संचालक: आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।

अब हम प्रश्न और उत्तर सत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पहली पंक्ति में विंडएकर के लंडस्ट्राम से है। कृपया पूछें।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: क्या हम पूछ सकते हैं कि आपके निजी क्षेत्र की कितनी प्रतिबलित पूँजी से ब्याज अर्जित हुआ है और ऋण पूँजी कितनी है?

राजीव शर्मा: निजी क्षेत्र का कुल ऋण मोटे तौर पर 44,000 करोड रूपए है अर्थात मेरी ऋण परिसंपत्ति बही का 17 प्रतिशत

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: इसमें से कितना उद्ग्रहित ब्याज बनाम ऐसी ऋण पूँजी से है जो मूल रूप से इन परियोजनाओं को दिया गया था।

एन. बी. गुप्ता: यह ऋण परिसंपत्ति है। एनपीए (एनपीए के अंतर्गत परिसंपत्ति) होने के कारण, ब्याज से होने वाली आय का लेखाकरण नहीं किया जाता है। इसलिए इस मद में कुछ भी शेष नहीं है।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: आप निर्माण के दौरान ब्याज कमा रहे हैं?

एन. बी. गुप्ता: अधिकांश परियोजनाएँ ऐसी परियोजनाएँ हैं जिनका प्रारंभण हो चुका है और यहाॅ तक कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए भी जो खाते एनपीए बन जाते हैं हम लोग केवल प्राप्त नकदी के आधार आय का लेखाकरण करते हैं, इसलिए जहाॅ-जहाॅ नकदी प्राप्त नहीं हुई है वहाॅ उस आय का लेखाकरण नहीं किया गया है। यह 44,000 करोड़ शुद्ध रूप से ऋण का बकाया है इसका कोई ब्याज घटक नहीं है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: केवल उत्शुकतावश जनता चाहता हूँ कि क्या ब्याज की राशि तुलन पत्र के कुछ अन्य खातों में दर्शाई गई है या इन ऋणों के अतिरिक्त कोई अन्य उद्ग्रहण नहीं है?

पीएफसी कर्मचारी: तुलन पत्र पर ऋण परिसंपत्ति के अंतर्गत कुछ 2,62,000 करोड़ फिर भी केवल पूँजी के रूप में है, उद्ग्रहित ब्याज भी वर्तमान परिसंपत्तियों में होगा।

राजीव शर्मा: प्रतिबलित परिसंपत्तियों के संबंध में हम कोई ब्याज नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: प्रारंभण किए जा चुके निजी क्षेत्र के संयत्रों के लिए क्या आप बता सकते हैं कि लोड फैक्टर या पीएलएफ क्या है?

राजीव शर्मा: पीएलएफ कुछ मामलों में 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत/70 प्रतिशत तक भी भिन्न-भिन्न होता है। इसका कारण यह भी है कि 44,000 करोड़ परिसंपत्तियों में से 14,000 करोड़ निजी क्षेत्र के ऋण नियमित रूप से अपनी देयताएँ चुकाते हैं और हम कोई मुद्दा नहीं देखते हैं, परंतु शेष निजी क्षेत्र का 30,000 करोड़ रूपए एनपीए श्रेणी के अंतर्गत आता है या पुनर्संरचित मानक श्रेणी या मानक श्रेणी के अंतर्गत आता है।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: जिन प्रतिबलित परियोजनाओं का आपने उल्लेख किया, उनमें से कितनी परियोजनाओं को निश्चित औसत का पीपीए कवरेज प्राप्त है। क्या आप

बता सकते हैं कि कितनी परियोजनाओं में कम से कम माना 50 प्रतिशत पीपीए है या उनका वह स्तर है जिससे आपके मतानुसार वे अपना ऋण चुका सकेंगी?

राजीव शर्मा: इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएँ प्रारंभ हो चुकी हैं, मोटेतौर पर 10,000 मेगावाट की क्षमता पहले ही प्रारंभ हो चुकी है इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएँ पीपीए वाली और 70 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएँ एफसीए वाली हैं।

पीएफसी कार्मिक: मेगावाट के रूप में यह 19,500 मेगावाट है, यह वह ऑकड़ा हे जो 30,000 करोड़ से संबंधित है, जिसमें से 50 प्रतिशत पीपीए वाली हैं, ऐसा हमारा कहना है।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: मैंने पाया कि वे प्रतिशत एनसीएलटी पुनर्संरचना के लिए हैं?

पीएफ कार्मिक: यह एनपीए और 30,000 करोड़ रूपए के पुनर्संरचित खाते के लिए है।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: सम्पूर्ण प्रतिबलित परिसंपत्तियॉ 50 प्रतिशत पीपीए से अधिक हैं, 50 प्रतिशत एफएसए से अधिक हैं और परियोजना दर परियोजना आधार पर हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सभी 50 प्रतिशत के आस-पास हैं या आपके पास कुछ ऐसा है जो 100 प्रतिशत है या कुछ ऐसा है जो शून्य है।

पीएफसी कार्मिक: यह संभव है कि यह संपूर्ण आधार पर हो परंतु एक ऐसी परियोजना हो सकती जिसकी कोई पीपीए न हो और ऐसी दूसरी परियोजना हो सकती है जिसकी 100 पीपीए हो।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: क्या आप ऐसी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिनकी पीपीए नहीं है, कितनी संख्या में परियोजनाओं की पीपीए नहीं है या कितने मेगावाट पर्याप्त हैं?

पीएफसी कार्मिक: हम इसके बारे में अलग से जानकारी दे सकते हैं परंतु कुछ ऐसी परियोजनाएँ भी होंगी जिनकी पीपीए या एफसीए नहीं होंगी। उनकी संख्या बहुत कम होगी।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: इन सभी प्रतिबलित परिसंपत्तियों को पारित कर देने के बाद क्या आपकी कोई अपेक्षा है। लंबे समय में आपका सामान्य विस्तार या एनआईएम क्या होगा जिससे आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें।

पीएफसी कार्मिक: जैसा कि हमने बताया, वर्तमान में निजी क्षेत्र का 'एक्सपोजर' केवल 17 प्रतिशत है जिसमें से केवल 30,000 प्रतिबलित है और यदि इस प्रतिबलन का समाधान हो जाता है तो प्रभाव इस दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं होगा कि यह 30,000 करोड़ परियोजनाएँ हमारी ऋण परिसंपत्ति का बड़ा हिस्सा नहीं बनतीं।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: क्यों?

राजीव शर्मा: क्योंकि हामरी ऋण बही में दर्शाया गया 83 प्रतिशत सरकारी जनोपयोगी संस्थाओं के लिए है जहॉ कोई वित्तीय प्रतिबलन नहीं है, मुझे नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र का एक्सपोजर बहुत कम है, वह केवल 17 प्रतिशत है जिसमें से 14,000 करोड़ पहले से ही अच्छा कर रहे हैं और हम इन निजी क्षेत्र के डेवलपरों से नियमित रूप से सेवा संबंधी देयताएँ (सर्विसिंग ड्यूज) प्राप्त कर रहे हैं।

राजीव शर्मा: हमारे पास केवल 30,000 करोड़ एक्सपोजर के इश्यू हैं परंतु इनमें से कुछ परियोजनाओं के पहले से ही पीपीए हैं, इनमें से कुछ के एफसीए हैं यहॉ तक कि इन परियेजनाओं का पुनरुद्धार करते समय भी हम अधिक हेयरकट की अपेक्षा नहीं करते।

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: क्या कारण है कि आप स्टील सेक्टर से संबंधित हेयरकट की राशि के बारे में स्पष्ट रूप से आशान्वित हैं। यह 50 प्रतिशत हेयरकट कहॉ हुआ है?

राजीव शर्मा: हम बहुत अधिक आशान्वित है क्योंकि ग्रिड में मॉग आज यथार्थपरक नहीं है, यह दबी हुई मॉग है। यदि आप विद्युत विनिमय के ऑकड़ों पर दृष्टिपात करें तो 10 से 15 वर्षों के दौरान बिजली की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और अब गर्मी आ रही है इसलिए मॉग और बढ़ेगी इसलिए सिस्टम में और मॉग होगी और व्यस्ततम समय की दरें 7 रूपए प्रति यूनिट की दर पर पहुँच जाएंगी, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रतिबलित परियोजनाएँ जिनकी पीपीए नहीं है, वे बाजार में अपनी बिजली अच्छी दरों

पर बेच सकती हैं और इससे हमें लाभ होने की संभावना है और कम मॉग का यह परिदृश्य लंबे समय तक बना नहीं रहेगा।

सरकार ने शक्ति की एक नई स्कीम भी अधिसूचित की जिसके अंतर्गत उन संयंत्रों का एफएसए प्राप्त हुआ जिनके पास एफएसए नहीं था, उन्हें इस स्कीम के तहत कायेला प्राप्त हुआ यदि उनके पास पीपीए था।

अब, सरकार शक्ति स्कीम के अंतर्गत एक नई स्कीम ला रही है। उन परियोजनाओं के लिए बोली शुरू की जाने वाली है जिनकी पीपीए नहीं है, वे भी कोयला प्राप्त कर सकती हैं। इससे विद्युत सेक्टर के परिदृश्य में और सुधार होगा और मॉग बढ़ रही है क्योंकि सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार इस देश के प्रत्येक परिवार, ग्रामीण या शहरी, को जोड़ने का प्रस्ताव करती है जो बिजली से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में और मॉग बेढ़ेगी क्योंकि जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, लोगों की आकांक्षाएँ बढ़ेंगी और सिस्टम में और मॉग आएगी। वे (विद्युत मंत्रालय) प्रतिबलित परिसंपत्तियों से 2500 मेगावाट बिजली की बिक्री की नई स्कीम ला रहे हैं। इस स्कीम को पहले ही राज्यों को अधिसूचित किया जा चुका है। हम नोडल एजेंसियॉ है और जैसा कि मैं समझता हूँ, हमें गुजरात से 5000 मेगावाट के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र से हमें 500 मेगावाट के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश से 1000 मेगावाट के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसलिए, अब राज्य आगे आ रहे हैं और हम राज्यों में मॉग का यथार्थपरक ऑकलन देख रहे हैं।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

एन्ड्रू लंडस्ट्राम: अब यदि आप निजी क्षेत्र के प्रतिबलित परिसंपत्तियों के ऋण पर दृष्टिपात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि व्यापार संघ के कुल लेनदारों का एनपीए या पुनर्संरचित परियेजनाओं के प्रति बकाया ऋण कितना है। इसलिए इन परियोजनाओं को कुल कितना उधार दिया जा रहा है?

राजीव शर्मा: इन ब्योरों के बारे में, हम आपकी और मुखातिब होते हैं क्योंकि इस समय हमारे पास ब्योरा नहीं है।

संचालक: धन्यवाद। दूसरा प्रश्न बिरला सन लाइफ के भावना मोहन की लाइन से हैं। कृपया प्रश्न पूछें।

भावना मोहन: हमारा एक ही प्रश्न है जो हमारी 3000 प्रबलित निजी परिसंपत्तियों के अंतर्गत 14 परियोजनाओं के संबंध में है जिसका उल्लेख करते हुए आपने कहा है कि वे आकार में 2000 करोड़ से कम हैं। इनकी कुल राशि कितीन होगी?

पीएफसी कार्मिक: यह लगभग 4500 करोड़ होगी।

भावना मोहन: केवल स्पष्टीकरण के लिए कुल 30,000 करोड़ में से केवल 4500 करोड़, 2000 करोड़ से कम है, इसलिए शेष 2000 से अधिक की होगी और इसलिए क्या 01 सितंबर, 2018 की समय सीमा उन पर लागू होगी।

पीपीएफसी कार्मिक: जी हॉ, बिलकुल सही है

संचालक: धन्यवाद। दूसरा प्रश्न शुभकाम वेंचर्स के संगम अय्यर की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

संगम अय्यर: केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। निजी क्षेत्र के एक्सएक्सपोजर में 30,000 विषम करोड़ के मानक को छोड़ कर आपने उल्लेख किया कि 55 प्रतिशत पीपीए वर्तमान में उनके पास उपलबध है। ठीक है? इसलिए इन 30,000 करोड़ के शेष की परिसंपत्ति गुणवत्ता के अनुसार दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य से कोई इन एक्सपोजर को क्या माने?

राजीव शर्मा: जिन परियोजनाओं के एफएसए नहीं है और जिन परियोजनाओं के पीपीए नहीं है, शक्ति स्कीम के अंतर्गत उनके लिए कोयले की नीलामी में भाग लेने का प्रावधान है। प्रथम ट्रांच पहले ही बोली में शामिल किया जा चुका है और जिन परियोजनाओं के पास पीपीए था उन्हें शक्ति स्कीम के तहत कोयला प्राप्त हुआ था। अगला ट्रांच उन परियोजनाओं के लिए नीलाम होने जा रहा है जिनके पीपीए नहीं हैं। इसलिए उन्हें कोयला प्राप्त होगा। इसलिए नीति मोर्चे पर बातें स्पष्ट होती जा रही हैं। ये मुद्दे एक-एक करके संबोधित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय इन प्रबलित परिसंपत्तियों के लिए 2500 मेगावाट विद्युत बोली की एक नई स्कीम ला रहा है। विद्युत वित्त निगम एक नोडल एजेंसी है मंत्रालय ।ने दस्तावेज को अनुमोदित कर दिया है। यह इस स्कीम को शीघ्र ही अधिसूचित करने जा रहा है और हमने राज्यों से मॉग को समेकित करने का प्रयास किया और हमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात से काफी

मॉगें प्राप्त हुई हैं और वे इस स्कीम में भाग लेने के लिए प्रति काफी उत्साहित है। इसलिए इससे सेक्टर में और खुलापन आएगा और हमें और पीपीए प्राप्त होंगे।

संगम अय्यर: महोदय, एक एनपीए मान्यता परिप्रेक्षय से धीरे-धीरे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये विभिन्न स्कीमें आ रही हैं तो क्या हम किसी प्रकार की बदतर स्थिति की आशंका देखते हैं? घोषणा की गई इन स्कीमों की आंतरिक क्षमताओं को देखते हुए और जिन्हें सेक्टर में शुरू किया जा रहा है आगे बढ़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य के संबंध में कैसे सोचा जाना चाहिए?

राजीव शर्मा: मेरा मानना है कि इसमें और सुधार होगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र का एनपीए अगले वर्ष विपरीत स्थिति में पहुँच जाएगा। इसलिए निजी क्षेत्र के लिए हमारे पास केवल 2.2 प्रतिशत निवल एनपीए रह जाएगा। और उस निजी क्षेत्र में भी, ईंधन संबंधी मुद्दों, पीपीए संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले छह महीनों में विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में परिवर्तन आएगा क्योंकि और मॉग बनेगी और आज के विद्युत विनिमय में आप देखेंगे कि पिछले 10 से 15 दिनों में विद्युत दर लगभग दोगुनी हो गई है और व्यस्ततम समय की दर 7 रूपए है और आगे गर्मी का मौसम आ रहा है इसलिए मॉग और बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि लाभ (मार्जिन) पर दबाव होगा या मेरे मार्जिन पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

संगम अय्यर: महोदय, राज्य मंत्री ने घोषणा की थी जिसमें प्रबलित एसईबी या प्रबलित डिस्कामों के लिए पीएफसी, आरईसी आदि के द्वारा और आगे बढ़ने की अपेक्षा नहीं की गई थी। इन्हें किस रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि बाहरी निवेशकों के परिपेक्ष्य में विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाने वाली घोषणाओं को देखते हुए प्रभाव के विस्तार को समझना बहुत कठिन होगा। इसलिए क्या आप उन डिस्कामों की स्थिति के बारे में हमारी सहायता कर सकते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने उल्लेख किया कि अनेक डिस्काम अभी भी बहुत अचछी स्थिति में है। परंतु ऐसा कहने से, पिछले दो सप्ताह की घोषणाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एक हताशापूर्ण मॉग है कि डिस्कामों की स्थिति उल्लेखनीय रूप से बदतर हुई है और इसलिए पीएफसी, आरईसी के इन खंडों को और उधारी या अग्रिम प्रशासित किया गया है इसलिए क्या आप इस संबंध में हमारी सहायता कर सकते हैं।

राजीव शर्मा: मैं इस प्रश्न को इस प्रकार संबोधित करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान एपीडीआरपी से शुरू कर आर-एपीडीआरपी और शहरी क्षेत्रों के लिए आईपीडीएस तक राज्य वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता बहाल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू-शुरू में राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और अब सौभाग्य योजना चल रही है। इसलिए इन सभी स्कीमों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण प्रणाली तथा विद्युत अवसंरचना के स्तर में सुधार लाना और उसका सुदृढ़ीकरण

करना है। विद्युत प्रणाली में आप जब भी अपने उप पारेषण वितरण प्रणाली के स्तर में सुधार करते हैं और उसका सुदृढ़ीकरण करते हैं, इससे कुल वाणिज्यिक और तकनीकी हानि में कमी लाने में मदद मिलती है। इससे ग्राहक को विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलती है, इससे उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है। हम एक सूचीबद्ध कंपनी हैं और निदेशक मंडल द्वारा अभिशासित होते हैं। हम मंजूरी संबंधी सभी निर्णय ले रहे हैं और इसका उल्लेख पहले ही कर दिया गया था जैसा कि हमारे नीतिगत दिशानिर्देश और सरकार की अनुमति के अनुरूप हमारे लेनदारों द्वारा अपेक्षा की गई है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हम किसी समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं।

आज की तारीख में अपने बोर्ड में हम निर्णय ले रहे हैं और वितरण कंपनियों की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियॉ कम करने के लिए इन वितरण कंपनियों से विचार-विमर्श कर विद्युत मंत्रालय ने कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के एक वक्र-पथ के संबंध में निर्णय लिया है कि किस वर्ष तक उन्हें इन हानियों को कम कर 15 प्रतिशत तक लाना है और अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में देश के कुछ शहरों में 10 प्रतिशत से भी कम कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियॉ हो रही हैं। इसलिए हमें सरकार की ईमानदारी तथा सरकारी पहलों को देखना चाहिए कि इन वितरण कंपनियों को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और हम इसके महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि हम आर-एपीडीआरपी के लिए नोडल एजेंसी हैं जिसके अंतर्गत

1405 शहरों को उन शहरों में आईटी समर्पित प्रणाली स्थापित करने के लिए लिया गया था जिनसे ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित होती है। इन 1405 शहरों में से 1370 शहर जीवंत हो गए हैं। आप ऊर्जा लेखापरीक्षा के ऑंकड़े देख सकते हैं, आप कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के स्तर के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इनमें से 80 प्रतिशत शहरों में एटी एंड सी (तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों) में कमी आई है।

संगम अय्यर: इस पृष्ठभूमि को देखते हुए वित्त वर्ष 19 में जाना, जहॉ ये सभी पहले या तो द्धितीयार्द्ध में अन्यथा कुछ लाभ देना शुरू करेगी। ऋण बही की वृद्धि किस प्रकार की है जो हम उस समय देख पा रहे हैं।

राजीव शर्मा: जैसा कि हमने सूचित किया है लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि थी। हमारी उम्मीद है कि हम उसे बनाए रख सकेंगे या यह इससे अधिक भी हो सकता है।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न फ्लारीनट्री एडवाइजर्स के विनोद मालवीय की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

विनोद मालवीय: महोदय, आपने जिस प्रबलित परिसंपत्ति समाधान के बारे में बात की है, क्या उसके बारे में कुछ ब्योरा दे सकते हैं। 2500 मेगावाट का आंरभिक टेंडर जो आप लाने जा रहे हैं। इसलिए उसके बारे में दो बातें। एक, आपने तीन राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में बात की

जिन्होंने रूचि दर्शाई है परंतु दूसरे पक्ष अर्थात आपूर्ति परिप्रेक्ष्य से कुल कितनी प्रबलित परिसंपत्ति है जिनका नई टेंडर के तहत समाधान किया जा सकता है जिसकी ओर हम देख रहे हैं।

पीएफसी कार्मिक: हमारी बही में प्रबलित परिसंपत्तियॉ लगभग 30,000 करोड़ हैं जो लगभग 19,000 मेगावाट के बराबर हैं।

विनोद मालवीय: मेरा अनुमान है कि फ्लोट किया जाने वाला यह टेंडर पूरे उद्योग पर लागू होगा, इसलिए मैं संपूर्ण उद्योग के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, कितनी प्रबलित परिसंपत्तियॉ इसके लिए बोली लगाएंगी?

राजीव शर्मा: शुरू-शुरू में यह 2500 मेगावाट के लिए होगा क्योंकि यह प्रायोगिक परियोजना है। एक बार इसमें सफल हो जाने पर पीटीसी की व्यापारिक भागीदारी के कारण शुरू-शुरू में यह प्रबलित परिसंपत्तियों के लिए होगा और हमें अच्छी दरों की उम्मीद है। इसलिए राज्य इस स्कीम में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यदि शुरू-शुरू में यह सफल हो जाता है तो इस मेगावाट में आगे बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है।

विनोद मालवीय: क्या बोली की प्रक्रिया के बारे में कुछ ब्योरे उपलब्ध करवा सकते हैं? क्या यह पूरी तरह से चार प्रशुल्क पर आधारित होगा या इसमें कुछ स्थिर भी होगा।

राजीव शर्मा: किसी प्रकार का स्थिर प्रशुल्क नहीं होगा। इसलिए यह नई स्कीम है और इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि इसे मंत्रालय अधिसूचित कर रहा है, यह मंत्रालय में अनुमोदनाधीन है, आपसे ब्योरों को साझा करने का यह उचित समय नहीं है।

विनोद मालवीय: टेंडर इसी महीने निकलेगा या यह......

राजीव शर्मा: पहले वे लोग फरवरी तक योजना बना रहे थे परंतु मार्च के अंत तक हम निश्चित रूप से यह निकल जाएगा क्योंकि मानव बोली दस्तावेज पहले विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। तब विशेषज्ञ समिति ने इसे विद्युत मंत्रालय को वापस कर दिया था। अब विद्युत मंत्रालय में यह अनुमोदन के स्तर पर है, फाइल अब सीधे मंत्री तक जाएगी। इसलिए हमारी उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक हमें अधिसूचना प्राप्त हो जाएगी और इसे ब्योरों में विस्तार से शामिल किया जाएगा कि योजना क्या है और इसका प्रचालन कैसे किया जाएगा।

विनोद मालवीय: मैं केवल इन सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता था, आपने कहा गुजरात ने 5000 मेगावाट में रूचि दर्शाई है, महाराष्ट्र -----

राजीव शर्मा: मुझे उनसे पत्र प्राप्त हुआ है। वे 5000 मेगावाट बिजली की दीर्घकालिक खरीद के बारे में सोच रहे हैं और मुझे महाराष्ट्र से भी इसी प्रकार का एक पत्र प्राप्त हुआ था और उत्तर प्रदेश से भी एक पत्र प्राप्त हुआ था। चूँकि मैंने उन सभी राज्यों को पत्र लिखा जो इसमें भाग लेना चाहते हैं जहाँ

इस नई स्कीम को ले जा रहे हैं। इसलिए कृपया हमें जानकारी उपलब्ध करवाएँ, इसलिए अधिकतर तीन से चार राज्य मुझे अच्छी तरह से याद हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात क्योंकि उन्हें इस स्कीम से कम दरों की उम्मीद है।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएचसी के प्रशांत जैन की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

आनंद: मैं इस ओर से आनंद बात कर रहा हूँ। मैं केवल 16000 मेगावाट की 22 परियोजनाओं को समझना चाहता हूँ जिन्हें हम बाहर एसडीआर में या 54ए में स्तरित करना चाहते हैं। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि शीर्षस्थ चार कौन हैं? शीर्षस्थ पॉच परियोजनाएँ कौन सी हैं? तथा उन एक्सपोजरों की मात्रा क्या हो सकती है और उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है।

राजीव शर्मा: इस स्तर पर मैं परियोजनाओं के नाम नहीं बता सकूँगा।

आनंद: क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि वहॉ केवल एक परियोजना थी।

राजीव शर्मा: निजी क्षेत्र में हमारा एक्सपोजर 44000 करोड़ है जिसमें से 14,000 करोड़ नियमित रूप से हमारी देयताएँ चुका रहे हैं और हमें कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। शेष 30,000 रूपए या तो एनपीए श्रेणी में है या पुनर्संरचित मानक श्रेणी में है या मानक श्रेणी में है और एनपीए लगभग 85,00

करोड़ रूपए हैं पुनर्संरचित मानक परिसंपत्तियाॅ मोटेतौर पर 15,500 करोड़ की है और मानक परिसंपत्तियाॅ लगभग 6,000 करोड़ रूपए की हैं।

आनंद: महोदय, क्या आप के एसके जैसी परियोजनाओं के बारे में कुछ बता सकते हैं जिसके बारे में दिसंबर तक प्रारंभण की बात कही गई थी। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है।

राजीव शर्मा: जी हाॅ, केएसके की तीसरी यूनिट दिसंबर में प्रारंभ की जा चुकी है इसलिए तीन यूनिटें पहले ही प्रारंभ हो चुकी हैं और चूँकि 50 प्रतिशत क्षमता प्रारंभ हो चुकी है इसलिए मानित प्रारंभण हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें चौथी यूनिट को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय मिल गया है। चौथी यूनिट पर जोर शोर से कार्य चल रहा है। इसी बीच डेवलपर के साथ एक बैठक हुई जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और ग्रामीण विद्‌युतीकरण निगम के अध्यक्ष भी मौजूद थे और उन्हें आरबीआई की नई स्कीम के बारे में अवगत करवाया गया। वे लोग नियमित रूप से इस संबंध में काम कर रहे हैं और अनुमान है कि समाधान के साथ वे बहुत जल्द हमारे पास आएंगे। समाधान की जानकारी हो जाने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपको सूचित करेंगे।

आनंद: और महोदय, ब्याज की दर के बारे में मेरा मानना है कि तीसरे प्रारंभण के बाद आपने ब्याज दर में कमी की होगी। तो क्या हम उससे पहले इसमें कमी कर सकते हैं।

राजीव शर्मा: जी, नहीं।

आनंद: और क्या आर. के. एम विद्युत के बारे में कुछ और बता सकते हैं जहाँ अधिक एक्सपोजर है।

राजीव शर्मा: इस माह आर. के. एम. विद्युत की अंतिम यूनिट का प्रारंभण हो रहा है और वे लोग छत्तीसगढ़ से अपना पीपीए वापस प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए वे पहले संघर्ष कर रहे थे और वे उत्तर प्रदेश को 375 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और मैंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है कि मेहरबानी कर अपना बकाया कम करें क्योंकि वे समय पर भुगतान नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष से भी बात की। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह अच्छी परियोजना है और हम इस परियोजना द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

आनंद: और हम इन परियोजनाओं से ब्याज प्राप्त कर रहे हैं?

राजीव शर्मा: हमें ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है।

आनंद: और इंडिया बुल्स, नासिक क्या आप कुछ और ब्योरा दे सकते हैं।

राजीव शर्मा: नासिक और अमरावती मेरा मानना है कि अमरावती को महाराष्ट्र से अनुसूची प्राप्त हो रही है। महाराष्ट्र बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है

क्योंकि उसके कुछ संयंत्र चल नहीं रहे हैं। इसलिए वे टेस्टा ऊर्जा, सिक्किम से बिजली प्राप्त कर रहे हैं और उन्होंने हमसे भी अनुरोध किया है कि उन्हें 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत है। इसलिए अमरावती को अनुसूचित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि उनका प्लांट लोड फैक्टर में सुधार लाकर 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक किया जा सकता है। ऐसा हमारा अनुमान है। नासिक के बारे में भी हमने 14 फरवरी को डेवलपर को आमंत्रित किया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष तथा अन्य नेता भी वहाॅ मौजूद थे।

उनको आरबीआई के 12 फरवरी के नवीनतम परिपत्र के बारे में बताया। तदनुसार, हमने उनसे कुछ समाधान के साथ वापस आने को कहा। हम उनसे समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं परंतु उनकी टीम हमारे अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वे हमसे नियमित रूप से वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हमें इन दोनों परियोजनाओं का समाधान भी प्राप्त होगा।

आनंद: और महोदय, लांको अमरकंटक?

राजीव शर्मा: कल हमारा लांको अमराकंटक के साथ विचार-विमर्श हुआ था।, दो यूनिटें पहले से प्रचालन में है और यूनिट तीन और चार के बारे में हमने ओएसडीआर प्रतिसंहृत किया था। परंतु चूँकि यह स्कीम अब वापस ली जा चुकी है, इसलिए हम अपने लेनदारों के साथ नए समाधान के बारे में कार्य

कर रहे हैं। हमने लेनदारों का सम्मेलन बुलाया है और हम इसे बहुत जल्दी अंतिम रूप देंगे।

आनंद: महोदय, लांको के बारे में हमारा विश्वास है कि लांको होल्डिंग कंपनी एनसीएलटी में है। इसलिए होल्डिंग कंपनी को एनसीएलटी में लेने से किस प्रकार समाधान होगा।

राजीव शर्मा: क्योंकि यह पृथक एसपीपी है और उस होल्डिंग कंपनी में हम एलएपीएल में लेनदार नहीं हैं क्योंकि दो यूनिटें पहले ही इस संयंत्र में प्रचालनाधीन है और हमें एक नया ईपीसी ठेकेदार प्राप्त करना है। इस स्तर पर मैं आपको यह नहीं बता सकता कि अंतिम समाधान क्या होगा। हमें लेनदारों की टीम से विचार-विमर्श करना है और तब हमें समाधान प्राप्त होगा।

आनंद: महोदय अंतिम प्रश्न, कुछ दिनों पहले अडानी को एमईआरसी से यह आर्डर प्राप्त हुआ कि उन्हें कोयले का अंतर 1200 करोड़ रूपए प्राप्त होगा। इसलिए क्या आप सोचते हैं कि यह अधिकांश घरेलू कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए समाधान हो सकता है?

राजीव शर्मा: यह विनियामकों पर निर्भर करता है क्योंकि बहुत से राज्यों में आईपीपी के ये मुद्दे काफी समय से लंबित हैं। कहीं-कहीं दो वर्षों से कहीं-कहीं तीन वर्षों से। अच्छा होगा यदि वे निर्णय लेने की अपनी प्रक्रिया में तेजी लाएँ और यह सभी कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए अचछा होगा।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

आनंद: और महोदय। कुछ ऐसे समाचार भी थे कि मुख्य रूप से न्येवेली लिग्नाइट एक ऐसे संयंत्र का अधिग्रहण करेगा जहॉ एसडीआर शुरू किया गया है जैसे जीएमआर छत्तीसगढ़। इसलिए उस संबंध में कोई नई बात महोदय।

राजीव शर्मा: बाध्यकारी बोलियॉ आमंत्रित की गई है और हम इसका यथाशीघ्र समाधान करने की योजना बना रहे हैं। मुझे सूचित किया गया है कि हम छह बाध्यकारी बोलियों की उम्मीद कर रहे हैं और एनएलसी भी उनमें से एक सहभागी है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ।

आनंद: अच्छी बात है, जिन परियोजनाओं के बारे में हमने चर्चा की है, मेरी दृष्टि में उनमें से केवल केएसके में हम ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। शेष परियोजनाओं में हमें ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है।

राजीव शर्मा: जी हॉ, यह सच है, मैं समझता हूँ कि यह सच है।

आनंद: महोदय, क्या आप निजी क्षेत्र संबंधी कुल ऋण पुस्तिका के बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। किस अनुपात में हम ब्याज नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

राजीव शर्मा: देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, निजी क्षेत्र में हमारा एक्सपोजर 44,000 करोड़ रूपए है। 14,000 करोड़ रूपए अर्थात मोटेतौर पर 32 प्रतिशत पर हम नियमित रूप से ब्याज प्राप्त कर रहे हैं और हमें उसका भुगतान भी प्राप्त हो रहा है। 14,000 करोड़ रूपए के बारे में कोई मुद्दा नहीं है। शेष 30,000 करोड़ रूपए या एनपीए श्रेणी में हैं या पुनर्संरचित

श्रेणी में हैं या मानक श्रेणी में हैं। एनपीए मोटेतौर पर 8,500 करोड़ रूपए है। इसलिए अब इस 8,500 करोड़ रूपए पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

मानक परिसंपत्तियॉ 6,000 करोड़ रूपए है, जहॉ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम लेखा में शामिल कर रहे हैं। पुनर्संरचित संपत्तियॉ 15,500 करोड़ रूपए हैं। इसमें से केएसके भी है जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं। आरकेएम में कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए पद मिश्रित बैग है।

आनंद: अच्छी बात है। क्या आप बता सकते हैं कि 30,000 करोड़ रूपए जैसी राशि पर कितने प्रतिशत ब्याज अर्जित होगा महोदय?

एन. बी. गुप्ता: वास्तव में लगभग 24,000 करोड़ रूपए पर हमें कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। केवल 6,000 करोड़ मिल रहा है जिसे हम हिसाब में शामिल कर रहे हैं।

आनंद: अच्छी बात है, महोदय। मोसर बेचर अनुपुर उस पोर्टफालियो का हिस्सा जहॉ से हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है।

राजीव शर्मा: अनुपुर में हमें नियमित रूप से भुगतान प्राप्त हो रहा है। हिंदुस्तान पावर और वास्तव में इसमें पीपीए भी शामिल है इस कारण इस परियोजना में कोई मुद्दा नहीं है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

आनंद: संभावित क्रेता कौन-कौन से हैं। ये एनसीएलटी या दूसरे लोग भी हो सकते हैं। कौन आगे आकर इन परियोजनाओं को खरीद सकते हैं या इनके लिए बोली लगा सकते हैं। आपको अनुमान है कि क्रेता कौन-कौन से हैं।

राजीव शर्मा: हो सकता है कि हमारा संयुक्त उद्यम भी बोली लगाए। वे अडानी, जेएसडब्ल्यू टोरेंट, न्येवेली लिग्नाइट हो सकते हैं। कुछ अवांछित लोग भी हो सकते हैं।

आनंद: महोदय, जिस संयुक्त उद्यम के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ और ब्योरा दे सकते हैं ऐसा कौन है?

राजीव शर्मा: देखिए, यह काफी आरंभिक स्तर पर है। हम एनटीपीसी, आरईसी और भेल तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से बात कर रहे हैं कि इन अच्छी परियोजनाओं के लिए एनसीएलटी में उचित मूल्य सुनिश्चित करने का यह अच्छा अवसर है और यदि हम उन्हें एक वर्ष या कुछ अवधि के लिए अपने साथ जोड़ सकें तो वे भविष्य में सोने की खान साबित होंगे क्योंकि बहुत जल्दी सेक्टर में मॉग का सृजन होने जा रहा है।

आनंद: इस बात को देखते हुए कि समाधान के लिए केवल 180 दिन या 6 माह शेष है, क्या आप समझते हैं कि इस अवधि में हम कोई संयुक्त उद्यम बना सकते हैं और सहभागी बन कर उससे पहले बोली लगा सकते हैं।

राजीव शर्मा: जी हॉ, हम बहुत आशान्वित है।

आनंद: और महोदय, आप संयुक्त उद्‌यम में कितन पण या पूल की बड़ी मात्रा की योजना बना रहे हैं? क्या इसका कोई ब्योरा है?

राजीव शर्मा: हम लोग विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस स्तर पर मैं आपको नहीं बता सकता। संयुक्त उद्‌यम अंतिम रूप में किस प्रकार का होगा और प्रत्येक सहभागी की कितनी साम्पा सहभागिता होगी। मैं नहीं बता सकता।

आनंद: क्या इस संबंध में मोटा अनुमान बता सकते हैं।

राजीव शर्मा: अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद हम इसके बारे में आपको बताएँगे।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस के सृजन सिन्हा की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

सृजन सिन्हा: मैं यह जॉच करना चाहता हूँ कि मुंद्रा विद्‌युत परियोजनाओं में टाटा या अडानी के साथ हमारा कैसा संपर्क है।

राजीव शर्मा: जी नहीं, हमारे पास नहीं है।

सृजन सिन्हा: और समूह स्तर पर क्या हमारा किसी प्रकार का एक्सपोजर है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

राजीव शर्मा: टाटा के साथ हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है। अडानी ने हमें पूर्व भुगतान कर दिया। इसलिए आज की तारीख में कोई एक्सपोजर नहीं है।

सृजन सिन्हा: अच्छा, यह बहुत बड़ी बात है। मैं प्रबलित परिसंपत्ति के बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ इसलिए जब मैं आपके जीएनपीएस पर दृष्टिपात करता हूँ तो यह लगभग 14,000 करोड़ रूपए 15,000 करोड़ रूपए और पुनर्संरचित लगभग 56000 करोड़ रूपए है। इससे बाहर की प्रबलित परिसंपत्ति की मात्रा क्या है। कोई एसडीआर 54ए या इसके बाद कुछ भी 70,000 करोड़ रूपए, 71,00 करोड़ रूपए है।

राजीव शर्मा: जी नहीं केवल स्पष्टीकरण के लिए हमारा निजी क्षेत्र का एक्सपोजर 44,000 करोड़ रूपए हैं जिसमें से एक चौथाई 14,000 करोड़ नियमित रूप से हमारी देयताओं का भुगतान कर रहे हैं। और कोई मुद्दा नहीं है। शेष 30,000 करोड़ रूपए हैं। जिसमें से 8,500 करोड़ एनपीए में है। पुनर्संरचित मानक परिसंपत्तियॉ 15,500 करोड़ रूपए हैं और मानक परिसंपत्तियॉ 6000 करोड़ रूपए हैं। यही ब्योरा है।

सृजन सिन्हा: तो क्या एसडीआर और एसडीआर के बाहर या 54ए तथा पुनर्संरचित मानक में परस्पर अच्छादन है?

राजीव शर्मा: मेरा मानना है कि वे पुनर्संरचित मानक परिसंपत्तियों के अंतर्गत हो सकते हैं।

सृजन सिन्हा: पुनर्संरचित मानक से बाहर क्या कोई एसडीआर या 54ए है।

राजीव शर्मा: मेरा मानना है कि वे सब मिलाकर 15,500 करोड़ के अंदर होंगे।

प्रबंधन: आपका प्रश्न है कि कया एसडीआर के अंतर्गत कोई मानक परिसंपत्तियॉ है?

सृजन सिन्हा: ठीक है।

राजीव शर्मा: इंडिया बुल्स और डान्स एनर्जी।

सृजन सिन्हा: और उसकी मात्रा क्या होगी?

राजीव शर्मा: मात्रा, 2500 करोड़ रूपए होगी।

सृजन सिन्हा: ठीक है 2,500 करोड़ रूपए और मेरा अंतिम प्रश्न ब्याज को विपरीत करने के संबंध में है जैसा कि आपने एसडीआर या 54ए के 10,000 करोड़ रूपए से संबंधित तिमाही में किया। इसमें कहा गया है कि तिमाही के लिए 683 करोड़ रूपए हैं और 794 करोड़ रूपए 31.12.2017 को समाप्त नौ माह के लिए है। इसलिए 653 करोड़ रूपए क्या तिमाही के ब्याज के रूप में है। मैं नोटों का संदर्भ दे रहा हूँ।

एन. बी. गुप्ता: देखिए इस 653 करोड़ रूपए में से 450 करोड़ पूर्ववर्ती तिमाही के लिए है। इस तिमाही के लिए यह मात्रा 203 करोड़ रूपए हैं।

सृजन सिन्हा: ठीक है, पूर्ववर्ती तिमाही के लिए 450 करोड़ रूपए इसलिए आपने स्थिति विपरीत कर दी है। इसलिए एसडीआर और एस 4ए में ब्याज को मान्यता देने की क्या नीति है।

एन. बी. गुप्ता: देखिए, वही बात है, यदि मुझे 90 दिनों में अभी धनराशि मिल जाती है तो यह 120 दिन है। इसलिए हम वास्तविक आधार पर मान्यता देते हैं। 120 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने पर यह नगद आधार पर होगा। यहॉ तक कि पहले भी ब्याज चक्र विपरीत हो जाएगा।

संचालक: धन्यवाद। अगला आईडीएफसी सिक्योरिटीज के माहरूख अडाजानिया की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

माहरूख अडाजानिया: संसदीय पैनल रिपोर्ट में 34 विद्‌युत परियोजनाओं की सूची में अडानी पूर्वा पाश्चिम और अडानी महाराष्ट्र का नाम भी लिया गया है। क्या ये वास्तव में प्रबलित हैं और क्या उन्हें संसदीय पैनल समाधान प्रक्रिया तक पहुँचना है।

राजीव शर्मा: हम लोग वहॉ नहीं है

माहरूख अडाजानिया: क्या आपको कुछ अनुमान है, महोदय

राजीव शर्मा: नहीं मुझे कोई अनुमान नहीं है। मैं संसदीय पैनल की सिफारिशों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

माहरूख अडाजानिया: अच्छी बात है, महोदय, यदा-कदा ऐसी बातें होती है। अभी कुछ देर पहले भी आपने ऐसी बात की, एनटीपीसी द्वारा कुछ संयंत्रों का अधिग्रहण। यहॉ तक कि भारतीय स्टेट बैंक ने भी बहुत समय लेने के लिए उनकी आलोचना की है, तो वास्तव में क्या रोक रहा है।

राजीव शर्मा: मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे मतानुसार एनटीपीसी वह उचित एजेंसी है जो इस संबंध में टिप्पणी कर सकती है क्योंकि वे इस प्रक्रिया को काफी समय से कर रहे हैं इसलिए उन्हें उत्तर देना है।

माहरूख अडाजानिया: और महोदय के अनुसार?

राजीव शर्मा: इसका उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं होगा।

माहरूख अडाजानिया: अच्छी बात है और रत्नागिरी विद्युत परियोजना के अनुसार?

राजीव शर्मा: अलग हटने (विसंबद्धन) को एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

माहरूख अडाजानिया: जी हॉ, इसी प्रकार इसके स्तर में सुधार किया जाता है।

एन. बी. गुप्ता: एक वर्ष बाद, एक विशिष्ट अवधि है: वह अवधि बीत जाने पर इसलिए मेरा मानना है कि अगले वर्ष तक इसके स्तर में सुधार हो जाएगा।

माहरूख अडाजानिया: इसलिए अब विसंबद्धन को अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसलिए अब से एक वर्ष या इसी प्रकार की अवधि या पूरी धनराशि

राजीव शर्मा: जी हॉ, पूरी धनरिश

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएफसी के आनंद लाधा की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

आनंद लाधा: इस तिमाही में शून्यता बहुत तेजी से आई। इसलिए क्या आप कुछ बता सकते हैं कि ब्याज में हमें किस प्रकार की विपरीत स्थिति देखने को मिलती है और इमारे लिए शून्य की लगातार स्थिति क्या होगी या आप हमें लाभ पक्ष की ओर भी मार्गदर्शन दे सकते हैं।

एन. बी. गुप्ता: क्या आप दोहरा सकते हैं?

आनंद लाधा: यह तीसरी तिमाही शून्य थी और बड़ी तेजी से 2700 करोड़ रूपए से 1800 करोड़ रूपए तक नीचे आ गई है इसलिए क्या आप कुछ बता सकते हैं कि इस तिमाही ब्याज में किस प्रकार का उल्टफेर या गैर-

उद्ग्रहण हुआ है और हमारे लिए शून्य की सतत स्थिति क्या होनी चाहिए।

एन.बी. गुप्ता: इस तीसरी तिमाही में 653 करोड़ रूपए की स्थिति विपरीत हुई हैं।

आनंद लाधा: 653 करोड़ रूपए।

एन. बी. गुप्ता: जी हॉ, इसकी स्थिति विपरीत हो गई है। 653 करोड़ रूपए में से लगभग 450 करोड़ रूपए पिछली तिमाही से संबंधित है और इस तिमाही के लिए यह केवल लगभग 203 करोड़ रूपए हैं।

आनंद लाधा: महोदय, आगे बढ़ते हुए हमारे लिए शून्य की सतत स्थिति क्या होगी?

एन. बी. गुप्ता: हमने उल्लेख किया है कि अधिकांश प्रबलित परिसंत्तियों से हमें कोई आय नहीं हो रही है। हमारा मानना है कि हम भविष्य में भी इस स्थिति को बनाए रखेंगे।

आनंद लाधा: अच्छी बात है। इस तिमाही में हमारा शून्य 1800 करोड़ रूपए था और 450 करोड़ रूपए के ब्याज का उल्टफेर पिछली तिमाही से संबंधित है इसलिए सतत स्थिति आधार पर कम से कम हमें 2,200 करोड़ से 2,300 करोड़ शन्य मानना चाहिए यदि प्रत्येक बात वही रहती है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

एन. बी. गुप्ता: तीसरी तिमाही में हमारा शून्य निवल ब्याज 1966 करोड़ रूपए था इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें चौथी तिमाही में भी उसे बनाए रखने की स्थिति में होना चाहिए।

आनंद लाधा: जी नहीं, इस 1900 करोड़ रूपए में से इस तिमाही में 650 करोड़ रूपए का विपर्पण था। उस पर 450 करोड़ रूपए पिछली तिमाही से संबंधित है। इसलिए आदर्श रूप में हमारा शून्य सतत स्थिति आधार पर होना चाहिए और यह 2,300 करोड़ के आस-पास होना चाहिए।

एन. बी. गुप्ता: देखिए ये गणितिय ऑकड़े है, निश्चित रूप से इन्हें ऊपर जाना चाहिए।

आनंद लाधा: एक अंतिम बात जिसका आपने उल्लेख किया, वह है कि रत्नागिरी विद्युत परियोजना को विसम्बद्ध कर दिया गया है। इसलिए आपका जो भी ऋण होगा वह या तो विद्युत परियोजना को हस्तांतरित हो जाएगा या एलएनजी परियोजना को हस्तांतरित हो जाएगा।

राजीव शर्मा: मेरा मानना है कि हम दोनों में हैं।

आनंद लाधा: इसलिए महोदय, दोनों कंपनियॉ कोई खास हानि नहीं पहुँचा पाएंगी?

एन. बी. गुप्ता: परंतु हमारे पास पहले से ही पर्याप्त प्रावधान हैं। हानि होगी, इसमें कोई शक नहीं है परंतु हम पहले ही पर्याप्त प्रावधान कर चुके हैं इसलिए चौथी तिमाही में बहुत अधिक हानि का अनुमान नहीं है।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न रिद्धि कैपिटल के रजत सेतिया वाली पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

रजत सेतिया: केवल एक प्रश्न, प्रावधान करने की आवश्यकता के संबंध में नए मानदंडों के अनुसार एक बार का ऋण एनसीएलटी को जाता है।

प्रबंधन: देखिए सामान्य एनपीए नियम सभी एनसीएलटी मामलों पर लागू होगा। उच्चत्तर प्रावधान या अन्य किसी प्रावधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है।

रजत सेतिया: इसलिए बुनियादी तौर पर यह 50 प्रतिशत प्रावधान है?

प्रबंधन: नहीं, 50 प्रतिशत नहीं

राजीव शर्मा: यह उन 12 प्रारंभिक खातों के लिए था जिन्हें एनसीएलटी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया था। दूसरे मामलों के लिए नहीं।

प्रबंधन: सामान्य एनपीए नियम लागू होंगे हालॉकि 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत।

एन. बी. गुप्ता: सामान्य परिसंपत्ति वर्गीकरण नियम लागू होंगे।

रजत सेतिया: समझ गया। यह 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के समान ही है।

एन. बी. गुप्ता: जी हॉ, बैंकों के लिए 15 प्रतिशत एनबीएफसी के लिए यह 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न, विंड एकड़ के स्नेहल अमीन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

स्नेहल अमीन: निजी क्षेत्र के ऐसे संयंत्रों के बारे में आपका एक्सपोजन क्या है जो राजकोषीय वर्ष 2018-19 के अंत के बाद में शुरू हो पाएंगे।

एन. बी. गुप्ता: निजी क्षेत्र को हमारा कुलन एक्सपोजर 44,000 करोड़ रूपए हैं और इन परिसंपत्तियों के 50 प्रतिशत से मोटे तौर पर 10,000 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है मेरा मानना है कि शेष 50 प्रतिशत कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर होगी।

स्नेहल अमीन: दूसरी बात, क्या आप बता सकते हैं कि अगले वर्ष में कितना प्रारंभण होगा और अब से एक वर्ष के भीतर कितना प्रारंभण होगा?

राजीव शर्मा: 40,000 रूपए की कुल उत्पादन परिसंपत्तियों में से 18,600 करोड़ पहले से ही प्रारंभ हो चुका है, शेष वर्ष 2017-18, 2018-19 में प्रारंभ होगा।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

स्नेहल अमीन: और वर्ष 2018-19 के बाद कितना शेष बचेगा।

पीएफसी कर्मचारी: देखिए हम वास्तव में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के 40,000 करोड़ रूपए के बारे में ब्योरा दें रहे हैं जिसमें हम कह रहे है कि 19222 करोड़ पहले ही प्रारंभण हो चुका है।

पीएफसी कर्मचारी: हम उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ष 2018-19 तक वे सभी प्रारंभ हो जाएंगी।

स्नेहल अमीन: अच्छी बात है, इसलिए निजी क्षेत्र के आपके सभी संयंत्र 18-19 तक प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए यदि निजी क्षेत्र के व्यापार संघ में योगदान करते हैं तो क्या आप व्यापार संघ के सबसे बड़े देनदार हैं और विशेष रूप से व्यापार संघ का कितना हिस्सा विद्युत वित्त निगम दे रहा है। क्या आमतौर पर यह व्यापार संघ का 10 प्रतिशत या 30 प्रतिशत है।

राजीव शर्मा: हम परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक की मंज़ूरी नहीं देते हैं। परंतु चूँकि हम विद्युत क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हैं, इसलिए आम तौर पर हम व्यापार संघ के सहभागी की सबसे बड़ी राशि को मंज़ूरी दे देते हैं। परंतु यह अलग-अगल परियोजनाओं में अलग-अलग होती है क्योंकि कुछ मामलों में हमारी प्रमुख भूमिका नहीं होती है, कहीं पर भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका प्रमुख होती है, कहीं पर आरईसी की भूमिका प्रमुख होती है या कुछ अन्य बैंकों की भूमिका भी प्रमुख होती है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

स्नेहल अमीन: अच्छी बात है क्या आपको मालूम है औसत तौर पर आपका प्रतिशत, व्यापार संघ का कितने प्रतिशत होगा। क्या आप औसतन आमतौर पर व्यापार संघ के 25 प्रतिशत होंगे।

राजीव शर्मा: जी हॉ, मैं समझता हूँ 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत उचित अंक है।

स्नेहल अमीन: इसके बाद आपने संयुक्त उद्‌यम का उल्लेख किया जो महान विचार प्रतीत होता है इसके बाद आपने केवल सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य देनदारों का उल्लेख किया। क्या संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी के लिए आप निजी क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं?

राजीव शर्मा: हम देखेंगे। शुरू-शुरू में हम सरकारी कंपनियों को संयुक्त उद्‌यम में भागीदार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम केवल सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ही बातचीत कर रहे हैं।

स्नेहल अमीन: अच्छी बात है और कृपया निश्चिंत रहें कि यह संयुक्त उद्‌यम आपको उन एनसीएलटी की परियोजनाओं में बोली लगाने की अनुमति भी देगा जहॉ के व्यापार संघ में आप लेनदार हैं?

राजीव शर्मा: हम इसी विषय पर काम कर रहे हैं। मैंने अपनी विधिक टीम से कहा है कि हम अपने परामर्शदाताओं से इन विधिक पक्षों पर बात कर रहे हैं कि इससे यह संयुक्त उद्‌यम विवर्जित नहीं होना चाहिए। यदि हम भी एनसीएलटी की परियोजनाओं में लेनदार हैं या एनसीएलटी के पास जाने

से पूर्व बोली प्रक्रिया में लेनदार हैं। परंतु जहॉ तक विधिक टीम से विचार-विमर्श का संबंध है, हम सही हैं। हम भाग ले सकते हैं।

स्नेहल अमीन: अच्छी बात है और तब आपके ब्याज का विस्तार होता है, राजकोषीय वर्ष 2018-19 में आप किन ब्याज के विस्तार की बात करते हैं।

राजीव शर्मा: यह कहना कठिन है परंतु हम वर्ष के दौरान ब्याज के विस्तार को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

एन. बी. गुप्ता: देखिए इस समय हमारा विस्तार लगभग 2.81 प्रतिशत है, ठीक है, और हमारी अपेक्षा है कि हमें 2.50 प्रतिशत से 2.81 प्रतिशत के बीच होना चाहिए।

स्नेहल अमीन: 2.5 प्रतिशत से 2.81 प्रतिशत के बीच? तो आप समझते हैं कि यह विस्तार नीचे जाएगा?

एन. बी. गुप्ता: जी हॉ, विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, बहुत से बैंक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सस्ती दर पर निधियॉ उपलब्ध करवा रहे हैं। हमें निश्चित रूप से उस कम दर का मुकाबला करना है।

राजीव शर्मा: और वास्तव में हमें उदय के बाद सरकारी जनोपयोगी संस्थाओं के लिए अपने ऋण के लगभग 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत का पुन: मूल्य निर्धारण करना पड़ा।

स्नेहल अमीन: ठीक है, क्या आपके इस 2.5 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत में वह लाभ भी शामिल है जो आपको वित्तीय लागत कम होने के कारण पहले से मिल रहा है?

एन. बी. गुप्ता: सच्चाई यह है कि हम उस कम हुई लागत को ऋण लेने वालों को भी दे रहे हैं क्योंकि हमारे ऋण पोर्टफोलियो का एक तिहाई पुन: व्यवस्थित किया गया है। इसलिए हम इन हितलाभों को अपने मौजूदा ऋण लेने वालों को भी दे रहे हैं।

स्नेहल अमीन: क्या कोई ऐसा विस्तार है जिस पर आप ऋण नहीं देंगे, जहॉ आप कहेंगे कि यह बहुत कम है, भले ही बाजार में वैसी स्थिति हो।

राजीव शर्मा: आमतौर पर न्यूनतम 200 बेसिक प्वाइंट बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

स्नेहल अमीन: न्यूनतम 200 बेसिक प्वाइंट?

राजीव शर्मा: यदि उधारकर्ता की गुणवत्ता A+ है तो वह सर्वोत्तम गुणवत्ता है।

स्नेहल अमीन: इसलिए मेरी सोच है कि कुछ वर्ष पूर्व न्यूनतम विस्तार प्रबंधन में 300 बेसिक प्वाइंट बनाए रखने की बात थी।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018

राजीव शर्मा: समय बदल गया है। हमारे व्यापार का आकार बढ़ रहा है, बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक हैं क्योंकि हमें अपने आपको बाजार की परिपाटियों के साथ जोड़ना होता है इसलिए हम उसको नजरअंदारज नहीं कर सकते हैं। 2 प्रतिशत की प्रतिशतता सबसे अच्छे ऋण लेने वाले के लिए है।

स्नेहल अमीन: मैं समझता हूँ कि बाजार का विसतार कम हुआ है परंतु सेक्टर के जोखिम में सार्थक ढंग से परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है? इसलिए किसी समय बाजार 100 बेसिक प्वाइंट के विस्तार तक जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि करने के लिए यह उचित काम है, आपके प्रतिफल और आपकी अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से अच्छी है। यही कारण है कि मुझे आश्चर्य है कि आपके द्वारा निर्धारित किया गया 200 बेसिक प्वाइंट क्यों और कैसे सहीं है और यदि बाजार 100 तक पहुँच जाता है तो क्या आप कहेंगे, बाजार 100 तक पहुँच गया है इसलिए हम 100 की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए हम बड़ी हानियों के बारे में बात करना बंद कर देंगे क्योंकि परियेाजनाओं के जोखिम में सुधार नहीं आ रहा है। इसलिए केवल बाजार दर क्यों?

राजीव शर्मा: यदि हम इसे जारी रखते हैं तो एनटीपीसी के समान एनटीपीसी द्वारा खड़ी की जाने वाली 2X660 मेगावाट की परियोजनाओं का पुन: निधियन करेंगे। यदि एनटीपीसी हमारे पास आता है, यदि मुझे अपनी परिसंत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना है और एनटीपीसी हमारे पोर्टफोलियो में आता है तो यह अच्छा है। यदि कुछ शीर्षस्थ नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करने वाले हमसे संपर्क करते हैं जब परियेाजना प्रारंभ हो चुकी है

तो कोई जोखिम नहीं है, उनका एनटीपीसी के साथ 25 वर्षों का पीपीए उनका सोलर पावर कॉर्पोरेशन के साथ 25 प्रतिशत पीपीए है। इसलिए उन मामलों में मैं उन अच्छे डेवलपर्स को अपनी ओर लाने और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्ति बन सके।

प्रबंधन: और मुख्य रूप पुन: मूल्य निर्धारण केवल सरकारी सेक्टर के ऋण में है जहॉ मेरा जोखिम बहुत कम है।

संचालनक: धन्यवाद। अगला प्रश्न हाई टेंपल कैपिटल के आदित्य मुंदड़ा से है। कृपया प्रश्न पूछें

आदित्य मुंदड़ा: आपकी नजर में अगले दो वर्षों के दौरान किस प्रकार के ऋण में वृद्धि होगी।

राजीव शर्मा: गत वर्ष हमारी वृद्धि 35 प्रतिशत थी और हमने 63,000 करोड़ रूपए वितरित किए और जैसा कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आईपीडीएस जैसी विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमों के तहत उप पारेषण, वितरण, स्तरोन्नयन और सुदृढ़ीकरण जोर-शोर से चल रहा है। इसके बाद सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक परिवार को मार्च, 2019 तक बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। इसलिए सिस्टम में और मॉग बढ़गी। इसलिए हमारी आर्थिक प्रगति के लिए विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण

अवसंरचना है और हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक बना रहेगा। इसलिए निश्चित रूप से में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच वृद्धि देख रहा हूँ।

आदित्य मुंदड़ा: जी नहीं, महोदय, वित्त वर्ष 18 की मंजूरी वित्त वर्ष 17 के 9 माह की मंजूरी से 30 प्रतिशत कम है इसलिए यह चिंता की बात है।

राजीव शर्मा: यह अलग-अलग वर्ष में भिन्न-भिन्न होता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस वर्ष हम अपनी मंजूरियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि यह हमारे एमओयू लक्ष्य में नहीं है परंतु हम वितरण पर अधिक ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हैं जिससे हमें आय होती है।

आदित्य मुंदड़ा: और महोदय, प्रश्न यह है कि आपने उल्लेख किया था कि लगभग 2,500 करोड़ की परिसंपत्तियॉ मानक श्रेणी में हैं परंतु वे पुनर्संरचित एसडीआर या 54ए में हैं। मेरा मानना है कि उनमें से एक इंडिया बुल्स था।

आदित्य मुंदड़ा: महोदय, इसलिए यह 2,500 करोड़ रूपए 6,000 करोड़ रूपए का भाग है जो 30,000 करोड़ रूपए में से मानक परिसंपत्ति है।

राजीव शर्मा: यह 6,000 करोड़ रूपए का भाग है, जी हॉ

आदित्य मुंदड़ा: इसलिए यह 6,000 करोड़ रूपए का भाग है?

राजीव शर्मा: जी हॉ

आदित्य मुंदड़ा: और महोदय, वित्त वर्ष 17 में परिसंपत्ति से आप 11.6 प्रतिशत है जो तीसरी तिमाही में है, यह लगभग 10.25 प्रतिशत है। इसलिए क्या आप आय पर और दबाव देखते हैं।

राजीव शर्मा: जो कुछ प्राप्त होना अपेक्षित था, वह प्राप्त हो चुका है। हम लोग उसे बनाए रखने में सफल होंगे।

आदित्य मुंदड़ा: अच्छी बात है, और इस हानि में प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण कमी हुई है जिसका उल्लेख आप कर रहे थे, और इसके कारण बैंकों से काफी प्रतिस्पर्धा है क्या यही कारण था?

एन. बी. गुप्ता: यह उदय के पुन: मूल्य निर्धारण के कारण था और यदि आप लेखाकरण टिप्पणियों को देखेंगे तो पाएंगे कि 450 करोड़ रूपए का ब्याज विपरीत स्थिति में पहुँच गया जो पूर्ववर्ती तिमाहियों से संबंधित है। इसलिए यह उसका एक कारण है।

आदित्य मुंदड़ा: और महोदय, यह मेरा अंतिम प्रश्न है आप ब्याज से कुल कितनी आय की उम्मीद रखते हैं। आप कह रहे थे कि केवल 650 करोड़ रूपए हैं जो इस तिमाही में विपरीत स्थिति में चला गया था, 450 करोड़ रूपए पिछली तिमाही का और 200 करोड़ रूपए इस तिमाही का। तो शून्य क्या है, हर

तिमाही के लिए आगे बढ़ने पर क्या यह 2,700 करोड़ रूपए के स्तर पर होगा जो पूर्ववर्ती वर्ष की सितंबर तिमाही में होगा।

एन. बी. गुप्ता: देखिए, हमारी उम्मीद है कि यह लगभग 2,200 करोड़ 2,300 करोड़ होगा।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न इंडिया कैपिटल के पीयूष गोयल की पंक्ति से है, कृपया प्रश्न पूछें।

पीयूष गोयल: महोदय, एक बात जो मैं समझता हूँ वह 30,000 करोड़ रूपए के प्रबलित निजी परिसंपत्तियों का है। इसमें से 4,500 करोड़ उस श्रेणी का है जो 2,000 करोड़ रूपए के कुल एक्सपोजर से कम का है और दूसरे 4,500 करोड़ पहले से ही एनसीएलटी में है। इसलिए शेष 21,000 करोड़ रूपए के बारे में क्या हमारे पास 01 सितंबर, 2018 की अंतिम तारीख से पहले कोई विकल्प है ताकि हम उन्हें ऐसे पुनर्संरचित कर सकें कि वे एनसीएलटी में न जा पाएँ या न जाएँ। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कितनी राशि को पुनर्संरचित किया जा सकेगा। आपने बताया था कि बहुत सी परियोजनाओं के लिए हम बातचीत में लगे हुए हैं परंतु मोटेतौर पर क्या आप हमें बता सकते हैं।

राजीव शर्मा: मैं आपको संख्या के बारे में नहीं बता सकता परंतु हम व्यापार संघ के अपने साझेदारों के साथ इन परियोजनाओं में इमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के साथ 14 फरवरी

की बैठक कर चुके हैं जिसमें आरईसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मौजूद थे और हम इन परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए नियमित रूप से संवाद करेंगे और जो भी सर्वोत्तम विकल्प होगा, हम अपनाएंगे। हम उस रास्ते पर जाने का प्रयास करेंगे।

पीयूष गोयल: परंतु महोदय, आंतरिक रूप से हमारे पास अंतिम तिथि से पहले किसी प्रकार पुनर्संरचित करने का विकल्प मौजूद है। ठीक है।

राजीव शर्मा: जी हॉ, हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ।

पीयूष गोयल: महोदय, मेरी ओर से केवल एक प्रश्न है। विद्युत मंत्रालय से हाल में प्राप्त निदेश जो हमें प्रबलित पूँजी के लिए उधार देने से रोकते हैं, उनका मोटेतौर पर हमारी बकाया मंजूरियों पर कितना असर पड़ेगा या क्या हमारे द्वारा पहले ही मंजूर की गई परियोजनाओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजवी शर्मा: जैसा कि आपने ही कहा हमें लिखित रूप में कोई निदेश नहीं प्राप्त हुआ है। हम बोर्ड द्वारा अभिशासित होने वाली कंपनी हैं और साथ ही कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) में कमी लाना विद्युत मंत्रालय का अंतिम लक्ष्य है जिसमें पीएफसी एक महतवपूर्ण उपकरण है। हम लोग, आईपीडीएस के लिए नोडल एजेंसी हैं जिसका अंतिम लक्ष्य एटी एंड सी हानियों में कमी लाना है और हम देश के 90 प्रतिशत से अधिक

शहरों में एटी एंड सी हानियों में कमी लाने में सफल हुए हैं। इसलिए मंत्री के वक्तव्य पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। परंतु हमारी मंजूरियॉ और वितरण पहले की तरह ही जारी हैं। वहॉ कोई समस्या नहीं है। हमारा बार्ड हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक बातों तथा हानि में कमी वक्रपथ को ध्यान में रखते हुए पूर्ण संसूचित, सुविचिारित दृष्टिकोण अपनाता है और हमारे मंजूरी पत्र में इसे उचित ढंग से कम किया जाता है और राज्य डिस्कामों से रूपरेखा ली जाती है। इसलिए यह सतत प्रक्रिया है। हमलोग पूरी तरह से इस तथ्य के प्रति भी वचनबद्ध हैं कि राज्य वितरण कंपनियों का स्वास्थ्य भी जितना शीघ्र हो सके बहाल किया जा सकें जिसमें हम विद्युत मंत्रालय की विभिन्न पहलों सहित विद्युत मंत्रालय के साथ भाग ले रहे हैं।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस के सृजन सिन्हा की पंक्ति से अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में है। कृपया प्रश्न पूछें।

सृजन सिन्हा: मैं देख रहा हूँ कि 6,748 करोड़ रूपए की ऋण परिसंपत्ति आपकी प्रस्तुति में प्रश्न 3 में एनपीए से पुनर्संरचित से मानक श्रेणी में स्तरोन्नयन की गई थी। परंतु जब मैं आपके पुनर्संरचित राज्य सेक्टर की परिसंपत्ति पर नजर डालता हूँ तो दिसंबर की तिमाही में उसमें तिमाही-दर-तिमाही कमी नजर आती है। तो क्या पुनर्संरचित बही से भी कोई स्तरोन्नयन किया गया था।

राजीव शर्मा: क्या हम इस मुद्दे पर आपके पास दोबारा आएँ? इस बीच आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

सृजन सिन्हा: नहीं, केवल यही प्रश्न है।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएफसी के आनंद लाधा की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

आनंद लाधा: क्या आप बता सकते हैं कि जिन परिसंपत्तियों या पोर्टफोलियो पर सतत राज्य आधार पर उद्ग्रहण हो रहा है उनसे औसत आय क्या है।

राजीव शर्मा: 10.95

आनंद लाधा: इसलिए महोदय, यह 10.95, 450 करोड़ के बाद का है या सतत है।

राजीव शर्मा: जी हॉ, विपर्यय के बाद

आनंद लाधा: और महोदय, क्या इसकी गणना कल ऋण पोर्टफोलियो पर की गई है या केवल उन परिसंपत्तियों पर जिनसे ब्याज उद्ग्रहित हो रहा है।

एन. बी. गुप्ता: केवल उन परिसंतत्तियों पर जिनसे हमें ब्याज मिल रहा है।

संचालक: धन्यवाद। अगला प्रश्न सएसपेन वेल्थ एडवाइजर्स के राजकुमार सिंहल की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

राजकुमार सिंहल: यह निजी क्षेत्र के 30,000 करोड़ रूपए के एनपीए के संबंध में है जिसमें हमने इसके कुछ भाग के एनपीए बन जाने के बाद ब्याज दर्ज नहीं किया है। कुल संचित राशि क्या है?

राजीव शर्मा: यह इस समय उपलब्ध नहीं है परंतु इसे हम बाद में उपलब्ध करवा सकते हैं।

प्रबंधन: यह अंतिम प्रश्न है।

संचालक: अंतिम प्रश्न बी एंड के सिक्योरिटीज के बंटी चावला की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

बंटी चावला: केवल एक स्पष्टीकरण। आपने कहा कि निजी क्षेत्र के 44,000 करोड़ हैं जिनमें से 14,000 करोड़ रूपए पर आपको नियमित रूप से आय प्राप्त हो रही है और 30,000 करोड़ रूपए के बाद आपने कहा 6,000 करोड़ रूपए मानक हैं। क्या ये एसडीआर के तहत मानक है। एसडीए भी मानक है परंतु क्या एसडीआर और 54ए के तहत। क्या ये 14,000 करोड़ रूपए की नियमित आय से भिन्न है।

राजीव शर्मा: जी हॉ, ये उससे भिन्न हैं।

बंटी चावला: इसलिए ये एसडीआर और 54ए के अंतर्गत हैं, ठीक है परंतु वे पुनर्संरचित के अधीन नहीं है?

राजीव शर्मा: जी हॉ।

संचालक: इसलिए अब एक अंतिम प्रश्न है? अगला प्रश्न क्वंटम सिक्येरिटीज के अमित राने की पंक्ति से है। कृपया प्रश्न पूछें।

अमित राने: मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

राजीव शर्मा: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

संचालक: धन्यवाद।

कुणाल शाह: अपना समय देने और ऐसी विस्तृत चर्चा करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भावी तिमाहियों के लिए मेरा हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।

संचालक: एडेलवेइस सिक्योरिटीज लिमिटेड की ओर से हम यह सम्मेलन समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब आप अपनी लाइनें काट सकते हैं।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

15 मार्च, 2018